क्रांति समय
हिन्दी दैनिक अखबार में विज्ञापन, प्रैस नोट, जन्म दिन की शुभकामनाएँ, या अपने विस्तार में किसी भी समस्या को अखबार में प्रकाशित करने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 9879141480

दैनिक
क्रांति समय

RNI.No. : GUJHIN/2018/75100

क्रांति समय
हमारे यहां पर एल.आई.सी., कार-बाईक-ट्रक का इन्सयोरेंशन, रेल टिकट, एयर टिकट बनवाने के लिए संपर्क करें:-
बी-4 घंटी वाला कॉम्पलेक्ष उधना तीन रास्ता, उडुप्पी होटल के बगल में, सूरत-394210
मो. 8980974047

संपादक : सुरेश मौर्या मो. 9879141480 सह संपादक : संदीप मौर्या
E-mail: krantisamay@gmail.com
सूरत, वर्ष: 1 अंक: 269, बुधवार, 24 अक्टूबर, 2018, पेज: 4, मुल्य 1 रु.
रजीस्ट्रड ऑफिस:- 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात
Email: krantisamay@gmail.com Web site : www.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

केरल नन बलात्कार मामले के गवाह की संदिग्ध हालात में मौत

होशियारपुर, एजेंसी। केरल में नन के साथ बलात्कार मामले के गवाह फादर कुरियाकोज कट्टुथारा सोमवार को पंजाब के होशियारपुर जिले के दसुया में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत मिले। कट्टुथारा आज सुबह अपने कमरे में बेसुध मिले थे, जिसके बाद उन्हें स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत लाया घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। उनके शरीर पर किसी तरह के चोट के कोई निशान नहीं है। कमरे में उलटी के निशान हैं। विसरा की रिपोर्ट को जांच के लिए भेजा जाएगा, जिसके बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पादरी को 15 दिन पहले ही दसुया के कैथोलिक चर्च में स्थानांतरित किया गया था। वह चर्च परिसर में रह रहे थे। स्कूल भी दसुया के धर्मपुर में गिरिजाघर के परिसर में स्थित है।

गाजियाबाद में सोसाइटी से 37 नेपाली लड़कियां बरामद, 3 आरोपी गिरफ्तार

गाजियाबाद। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र की एक सोसाइटी से 37 नेपाली लड़कियों के बरामद होने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस फिलहाल आरोपियों से पूछताछ करके कुछ अहम जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 17 पासपोर्ट, लैपटॉप एवं अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। पुलिस अधीक्षक (एसपी) सिटी श्लोक कुमार ने बताया कि इस मामले में केदारनाथ, रोमियो व ज्ञानेंद्र के खिलाफ विभिन्न धाराओं में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) वैभव कृष्ण ने बताया कि तस्करों का एक साथी, अनिल नेपाली, दुबई से युवक व युवतियों की डिमांड नेपाल में रह रहे गणेश को भेजता था। इसके बाद वह डिमांड के आधार पर लड़कियों को तैयार करके नेपाल से भारत में पकड़े गए तीनों आरोपियों के पास भेजते थे और फिर यहां से उन्हें दूसरे देशों में भेज दिया जाता था।

बरामद, 03 अभियुक्त गिरफ्तार। 17 पासपोर्ट एवं अन्य दस्तावेज बरामद।

उक्त सम्बन्ध में जानकारी देते हुए। पुलिस के अनुसार, इससे पहले दो अन्य लोगों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी, लेकिन उन्हें दोषी नहीं पाया गया। इसके चलते दोनों को छोड़ दिया गया। पुलिस के मुताबिक, फिलहाल सभी नेपाली युवतियों की काउंसलिंग की जा रही है जिसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करके कुछ अहम सुराग जुटा रही है। पुलिस आरोपियों से उनके अन्य साथियों के बारे में भी पूछताछ कर रही है।

स्वतंत्रता सेनानी अशफाक उल्ला खान की सोमवार को 118वीं जयंती के मौके पर इलाहाबाद में उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण करते स्कूली छात्र।

उप्र विधान परिषद के सभापति के बेटे की हत्या का मामला

मां ने ही की थी हत्या, गिरफ्तार

हत्या के आरोप में गिरफ्तार सभापति के बेटे अभिजीत यादव की मां मीरा यादव। अभिजीत यादव

लखनऊ। विधान परिषद के सभापति रमेश यादव के छोटे बेटे अभिजीत यादव उर्फ विवेक (22) की हत्या उसकी मां मीरा यादव ने ही की थी। एसएसपी के मुताबिक मीरा अभिजीत की शराब की लत से परेशान थी।शनिवार रात शराब के नशे में घर पहुंचे अभिजीत का मां से झगड़ा हुआ था। इस दौरान मां मीरा ने थप्पड़ मारने के साथ ही उसे धक्का दे दिया था जिससे दीवार पर सिर टकराने से अभिजीत बेहोश हो गया। इसके बाद मां मीरा ने दुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद दुपट्टे को चूल्हे में जलाने के बाद अवशेष नाली में फेंक दिये थे। हजरतगंज पुलिस ने मीरा को गिरफ्तार कर सोमवार को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से चूल्हा, क्रीम व दुपट्टे के अवशेषों को कब्जे में ले लिया है। दारुलशफा के न्यू बी-ब्लॉक फ्लैट नम्बर-137 में विधान परिषद के सभापति रमेश यादव की दूसरी पत्नी मीरा यादव अपने बेटे अभिषेक और अभिजीत यादव उर्फ विवेक के साथ रहती थी।

रविवार सुबह पुलिस को सूचना मिली कि अभिजीत यादव की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी। इस सूचना पर हजरतगंज पुलिस दारुलशफा पहुंची तो परिजनों ने अभिजीत की मौत को स्वाभाविक बताते हुए पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया।

परिजन अंतिम संस्कार के लिए शव लेकर बैकुंठ धाम के लिए निकल गये थे लेकिन शक होने पर पुलिस ने बीच रास्ते शव वाहन को रुकवाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या का राज खुल गया।

शहीद के अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले पत्नी ने दिया बच्ची को जन्म

बनिहाल, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में शहीद लांस नायक रणजीत सिंह के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए पैतृक गांव ले जाया गया। मंगलवार को पैतृक गांव में शहीद के अंतिम संस्कार से कुछ घंटे पहले उनकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। यह दंपति की पहली संतान है जो करीब 10 साल इंतजार के बाद हुई। लांस नायक सिंह जम्मू कश्मीर लाईट इंफैंट्री के उन तीन जवानों में एक थे जो रविवार को राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसैपैठियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गये थे। मुठभेड़ में दो सशस्त्र पाकिस्तानी घुसपैठिये, जिन्हें पाकिस्तान की बार्डर एक्शन टीम का सदस्य माना जा रहा है, भी मारे गए। तिरंगे में लिपटा 36 वर्षीय सैनिक सिंह का पार्थिव शरीर अखनूर गैरीसन में श्रद्धांजलि के बाद सोमवार को उनके पैतृक गांव सुलीगाम लाया गया। लेकिन देर हो जाने की वजह से परिवार ने मंगलवार सुबह अंतिम संस्कार का फैसला किया। अधिकारियों के अनुसार लेकिन आधी रात को उनकी गर्भवती पत्नी सीमू देवी को प्रसव पीड़ा होने लगी और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने सुबह करीब पांच बजे एक बच्ची को जन्म दिया। अधिकारियों के मुताबिक सीमू को अपने पति का अंतिम दर्शन कराने के लिए उनकी नवजात शिशु के साथ श्मसान घाट ले जाया गया। इस परिवार को जानने वाले एक स्थानीय निवासी विजय कुमार ने कहा, ''इन सैनिक ने अपनी पहली संतान के जन्म के लिए दस साल तक इंतजार किया लेकिन विधाता को अंत में कुछ और मंजूर था।

»»» चोकसी के लिए काम करती थी जेटली की पुत्री : राहुल

मेहुल मामले में इस्तीफा दें जेटली : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली की पुत्री बैंक घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के लिए काम करती थी जिस वजह से मेहुल की फाइल दबाए रखी गयी और उसे विदेश भागने दिया गया। गांधी ने सोमवार को ट्वीट किया अरुण जेटली की बेटी चोर मेहुल चोकसी के लिए पे-रोल पर काम करती थी। इसी कारण उसके वित्त मंत्री पिता ने फाइल दबाए रखी और उसे विदेश भागने दिया। आईसीआईसीआई के खाता संख्या 12170500316 पर उसे भुगतान किया गया। उन्होंने इसको लेकर मीडिया पर भी निशाना साधा और कहा यह दुखद है, मीडिया ने इस खबर को नहीं दिखाया। यह खबर देश की जनता तक नहीं पहुंच पायी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली को मेहुल चोकसी द्वारा किए गए बैंक घोटाले की जानकारी थी लेकिन पुत्री और दामाद के हित में कार्रवाई करने की बजाय उसके विदेश भगाने की साजिश की गयी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट और महिला कांग्रेस अध्यक्ष सुष्मिता देव ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि मेहुल चोकसी की जालसाज फर्म गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का काम जेटली की पुत्री सोनाली जेटली तथा दामाद जयेश बख्शी की फर्म ने लिया और इसके लिए 24 लाख रपए उन्हें दिए गए लेकिन बाद में जब सीबीआई ने मेहुल की कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज।

एक हफ्ते में दूसरी बार आशीष की जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने हयात रीजेंसी होटल में पिस्टल लहराने के आरोपी पूर्व बसपा सांसद राकेश पांडेय के बेटे आशीष पांडेय की जमानत याचिका मंगलवार को एक बार फिर खारिज कर दी। बता दें कि एक सप्ताह में यह दूसरी बार है जब आशीष की जमानत याचिका खारिज हुई है।

दिवाली पर पटाखे जलाने के लिए सिर्फ दो घंटे, दिल्ली एनसीआर में नहीं होगी बिक्री

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली और अन्य त्योहारों के अवसर पर पटाखे चलाने के लिए रात आठ बजे से 10 बजे (दो घंटे) की समय सीमा निर्धारित करते हुए देशभर में कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले ग्रीन पटाखे बनाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली एनसीआर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलेंगे, इनके अलावा यहां अन्य पटाखों की बिक्री नहीं की जाएगी और लड़ी वाले पटाखे बिल्कुल नहीं बिकेंगे। इन आदेशों का पालन स्थानीय थाना प्रभारी करवाएंगे, जिसमें विफल रहने पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की पीठ ने मंगलवार को दिए आदेश में ई-कॉमर्स वेबसाइटों को पटाखों की बिक्री करने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ अवमानना की सख्त कार्रवाई की जाएगी। शीर्ष अदालत ने वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के उद्देश्य से, देश में पटाखों के निर्माण और उनकी बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के लिए दायर तीन अबोध बच्चों अर्जुन गोपाल आदि की याचिकाओं पर यह आदेश दिया। ये याचिकाएं उनकी ओर से उनके अभिभावकों ने दायर की थी।

लाइसेंसदार ही बेचेंगे

पीठ ने कहा, निर्धारित सीमा के भीतर ही शोर करने वाले पटाखों की बाजार में बिक्री की अनुमति होगी और उन्हें सिर्फ लाइसेंसदार ही बेचेंगे।

लड़ी वाले पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि ये पटाखे सबसे ज्यादा शोर, ठोस कचरा और धुआं पैदा करते हैं। इसलिए ये नहीं बेचे जाएंगे।

सामुदायिक पटाखा केंद्र बनाएं

शीर्ष अदालत ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा कि वह दीपावली और दूसरे त्योहारों के अवसर पर दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सामुदायिक तरीके से पटाखे चलाने को प्रोत्साहन दे। एक सप्ताह में इस तरह के स्थानों का चयन किया जाए और जनता को इसके बारे में बताया जाए। ये स्थान शादी समारोह में पटाखे चलाने के लिए भी प्रयोग किए जाएंगे।

और सख्ती संभव

कोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण बोर्ड से 14 दिनों (दिवाली से सात दिन पूर्व तथा सात दिन बाद) का अध्ययन करने को कहा। वे देखेंगे कि वातावरण में बेरियम, अल्युमीनियम और आयरन तथा अन्य प्रदूषक तत्वों का क्या स्तर है। ये संस्थाएं अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देंगी और इन पर सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। कोर्ट ने कहा कि यदि स्थिति नहीं सुधरी तो और सख्त कार्रवाई के उपाए किए जाएंगे।

कोर्ट ने कहा कि स्टडी में यह सामने आया है कि 2016 में जब पटाखों पर कोई बैन नहीं था, दिल्ली में हवा में पीएम 2.5 (प्रदूषक कण) का स्तर दो से साढ़े तीन गुणा तक था। अक्तूबर 2017 में पटाखों पर आंशिक बैन के बाद पीएम 2.5 के स्तर में 39 फीसदी की कमी आई। साफ है कि पटाखों से पीएम का स्तर बढ़ता है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर सीधा असर डालता है।

नए साल और क्रिसमस के लिए आधा घंटा

कोर्ट ने नए साल और क्रिसमस के त्योहार के लिए पटाखे जलाने की अवधि मध्य रात्रि में 11: 55 से 12: 30 तक रखी है। इन त्योहारों पर इस समय सीमा के अंदर की पटाखे चलाए जाएंगे।

थानाध्यक्ष जिम्मेदार होंगे

प्रतिबंधित पटाखे चलाने और उन्हें निर्धारित सीमा के बाद चलाने देने की स्थिति में संबंधित इलाके के थाना प्रभारी जिम्मेदार होंगे। उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई भी की जाएगी।

स्कूलों में व्यापक अभियान चलाएं

कोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारें स्कूलों तथा कॉलेजों में अभियान चलाएं और छात्रों को पटाखों के नुकसान के बारे में शिक्षित करें।

पेसो फैक्टरियों पर निगाह रखे

कोर्ट ने पेसो (पेट्रोल तथा विस्फोटक सेफ्टी संगठन) से कहा कि वह ग्रीन पटाखे न बनाने वाली फैक्टरियों को बंद करवाए।

फैसले में संतुलन बनाया

शीर्ष अदालत ने इससे पहले कहा था कि पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध के मामले में इनके निर्माताओं की आजीविका के मौलिक अधिकारों और देश की सवा सौ करोड़ से अधिक आबादी के स्वास्थ्य के अधिकारों सहित विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होगा। कोर्ट ने कहा संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदत्त जीने का अधिकार सभी पक्षों पर समान रूप से लागू होता है और पटाखों पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाने के आग्रह पर विचार करते समय इसमें संतुलन बनाने की आवश्यकता है। पटाखा कारोबार में पांच लाख परिवार लगे हुए हैं और यह कारोबार सरकार को हर वर्ष 6000 करोड़ रुपये का राजस्व देता है। इसके बंद होने से लोगों के सामने रोजगार का संकट हो जाएगा।

इससे पूर्व आंशिक प्रतिबंध था

शीर्ष अदालत ने पिछले साल नौ अक्टूबर को दीपावली से पहले पटाखों की बिक्री पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया था और दीवाली परपटाखों की बिक्री की अनुमति दे दी थी। लेकिन बाद में न्यायालय ने कारोबारियों की याचिका खारिज करते हुए अक्तूबर, 2017 के अपने आदेश में किसी प्रकार की ढील देने से इनकार कर दिया था।

संपादकीय

''आजाद हिन्द फौज'

रतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुषों के योगदान को कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने भुला-बिसरा दिया था, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कांग्रेस की गलतियों को सुधारते हुए उनकी पुन: प्राण-प्रतिष्ठा कर रहे हैं। वास्तव में भाजपा की राष्ट्र की कल्पना में सुभाष और पटेल सटीक बैठते हैं। दोनों आक्रामक राष्ट्रवाद का प्रतिनिधित्व करते थे। जाहिर है कि इनके विचार भाजपा के विचार को ही ध्वनित करते हैं। जनमानस में सुभाष और पटेल का बहुत सम्मान है। मोदी सुभाष और पटेल को महत्त्व दे रहे हैं, तो इसका राजनीतिक लाभ भी उन्हें मिलेगा। दरअसल, भारत के वे लोग जो गांधी की अहिंसावादी नीति का समर्थन नहीं करते उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा और अखंडता की अक्षुण्णता बनाए रखने के लिए सुभाष की सैन्य शक्ति और युद्ध नीति पर ज्यादा विास है। ऐसे लोग अपने मन-मस्तिष्क में जिस प्रकार के महानायक की छवि देखते हैं, सुभाष उन्हें पूरा करते हैं। जनमानस के ऐसे महानायक को महत्त्व देकर भाजपा आम भारतीयों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। यही वजह है कि मोदी ने सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिन्द सरकार के गठन का पचहत्तरवां साल पूरे होने पर परंपरा से हटकर लाल किले पर विशेष कार्यक्रम को संबोधित किया। आजाद भारत के इतिहास का यह पहला अवसर था, जब किसी प्रधानमंत्री ने पंद्रह अगस्त के अलावा लाल किले पर झंडा फहराया हो। प्रधानमंत्री द्वारा सुभाष के करीबी सहयोगी लालती राम की ओर से भेंट की गई ''आजाद हिन्द फौज' की टोपी पहनना उनके कट्टर राष्ट्रवाद के प्रति निष्ठा का ही प्रगटीकरण है। सच है कि कांग्रेस ने भारतीय नायकों की उपेक्षा की है। पटेल जैसे राष्ट्रवादी नेता के मामले में भी कांग्रेस और उसकी सरकारों का उपेक्षापूर्ण रुख रहा है। बताने की जरूरत नहीं है कि कांग्रेस के संकीर्णवादी नजरिए के कारण ही उसका जनाधार सिकुड़ता जा रहा है। भाजपा देश के नायकों को महत्त्व दे रही है, तो कांग्रेस को ईर्ष्या हो रही है। उसे समझना चाहिए कि सुभाष, पटेल, अंबेडकर जैसे महानायक किसी दल के नहीं, देश की विरासत हैं, और उन पर सभी का बराबर हक है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास के इस तय को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आंदोलन के दौरान आगे चलकर गांधी और सुभाष के रास्ते भले अलग-अलग हो गए थे, लेकिन सुभाष के लिए गांधी उतने ही आदरणीय बने रहे जितने पहले थे।

ट्रंप की घोषणा

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह घोषणा भयभीत करने वाली है कि उनका देश शीत युद्ध के दौरान रूस के साथ की गई हथियार नियंतग्र संधि से अलग हो जाएगा। इससे विनाशक हथियारों की नई होड़ का खतरा पैदा हो रहा है। वस्तुत: 1987 में अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन तथा सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाच्योव ने मध्यम दूरी नाभिकीय शक्ति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि अमेरिका तथा रूस को 300 से 3,400 मील दूर तक मार करने वाली जमीन से छोड़े जाने वाली क्रूज मिसाइलों के निर्माण को प्रतिबंधित करती है। तब दोनों महाशक्तियों की ओर से शीत युद्ध का तनाव खत्म करने की कोशिश हो रही थी। उस दौरान हुई इस संधि से विश्व के बड़े भाग ने राहत की सांस ली थी। वास्तव में यह संधि अमेरिका और यूरोप तथा सुदूर पूर्व में उसके सहयोगियों की सुरक्षा में मदद करने वाली थी। इसकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। अमेरिका का आरोप है कि उसने तो इस संधि का पालन किया लेकिन रूस ने नहीं किया और चीन भी क्रूज मिसाइल बना रहा है। इसमें उसके पास संधि से अलग होने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस संधि की समय सीमा अगले दो साल में खत्म हो जाएगी। पहले अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने कहा था कि वे चाहते हैं कि उनका देश इस संधि से अलग हो जाए। अब ट्रंप ने नेवादा में घोषणा कर दी कि हम समझौते को खत्म कर इससे बाहर होने जा रहे हैं। वैसे, ट्रंप ने अभी इसमें एक गुंजाइश छोड़ी है। जैसे उन्होंने कहा कि जब तक रूस और चीन एक समझौते पर सहमत न हो जाएं तब तक हम समझौते को खत्म कर रहे हैं। इसका मतलब यह कि अगर रूस और चीन घोषणा कर दें कि हम नये सिरे से ऐसा समझौता करने के लिए तैयार हैं, रूस अमेरिका की बात मानने के लिए तैयार और न ही चीन। रूस ने कह दिया है कि अमेरिका की घोषणा उसकी विश्व की अकेली नियंतग्र महाशक्ति बनने के सपने से प्रेरित है, उसका मुख्य मकसद एकध्रुवीय दुनिया कायम करना है। वस्तुत: रूस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्रूज मिसाइलों के प्रति उसकी नीति क्या है? दुनिया नये शीत युद्ध में उलझे यह किसी के हित में नहीं होगा।

सत्संग

सकारात्मक पहलू

तुम्हारी आंतरिक सत्ता के विकास पर कार्य करना होता है। दोनों एक ही प्रक्रिया के अंग हैं। कैसे तुम्हें एक समग्र व्यक्ति बनाया जाए, उस सारी निस्सारता को, जो तुम्हें समग्र बनने से रोक रही है, कैसे नष्ट किया जाए। यह तो नकारात्मक पहलू है और सकारात्मक पहलू है कि कैसे तुम्हें प्रज्वलित किया जाए ध्यान से, मौन से, प्रेम से, आनंद से, शांति से। मेरी देशना का यह सकारात्मक पहलू है। बहुधा लोगों को सकारात्मक पहलू से तो कोई झंझट नहीं है। पर तुम्हें तो बचपन से ही झूठों के साथ पालन-पोषण किया गया है। पुराने समय में ऐसा सोचा जाता था कि जहां कहीं भी मांग होगी, पूर्ति अपने से हो जाएगी। अब, नियम यह नहीं है। अब नियम यह है कि यदि पूर्ति करने के लिए तुम्हारे पास कोई चीज है, मांग निर्मित करो। सदियों से आदमी को विास, सिद्धांत, मत बेचे गए हैं जो कि एकदम मिया हैं, झूठे हैं, जो केवल तुम्हारी महत्त्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस्य का प्रमाण हैं। तुम करना कुछ चाहते नहीं, और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो। और ऐसे लोग हैं, जो तुम्हें नक्शे, सरल विधियां देने को तैयार हैं, जितनी चाहो उतनी सरल विधि। बस परमात्मा का नाम लेते, सुबह उठ जाओ। कभी-कभी गंगा में डुबकी लगा आओ ताकि तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएं। सभी धर्मों ने ऐसी तरकीबें बना रखी हैं। काबा चले जाओ और सभी कुछ माफ कर दिया जाएगा। मुसलमान गरीब लोग हैं और वे गरीब हैं, अपने विासों के कारण। वे धन को सूद पर लेने या देने के खिलाफ हैं। अब सारा व्यवसाय सूद पर ही निर्भर है, तो उन्हें गरीब रहना ही होगा। और उन्हें बताया गया है कि जीवन में कम से कम एक बार काबा अवश्य जाना चाहिए तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। बस इतनी आसान विधियां। पंडित-पुरोहित तुम्हें सरल विधियां बताते हैं क्योंकि तुम आलसी हो। सच तो यह है कि तुम अपने अंतस की खोज के लिए कुछ करना ही नहीं चाहते हो। स्वर्ग कहीं बादलों में नहीं, तुम्हारे भीतर है। इसके लिए तुम्हें गंगा या काबा या गिरनार जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें केवल ''स्वयं' तक पहुंचने की जरूरत है। परंतु कोई पंडित-पुरोहित या तथाकथित धर्म नहीं चाहते कि तुम स्वयं तक पहुंचो, क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं की खोज पर निकलते हो, तुम सभी तथाकथित धर्मों-हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंधनों से बाहर आ जाते हो। उन सभी के बाहर आ जाते हो, जो मूढ़तापूर्ण और निर्थक है,क्योंकि तुमने स्वयं का सत्य पा लिया है।

''बॉटम ऑफ पिरामिड' नीतियों

ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस में कार्यरत कंपनियों में भारी विदेशी निवेश है। इस क्षेत्र में भी यह सूचना का प्रतिफल हो सकता है। जो पेमेंट रु ज्ञान से विकसित होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकेत विदेश में स्थित कंपनियों को अधिक विश्वस्त रूप से प्राप्त हो जाते हों और उसी का उपयोग ''बॉटम ऑफ पिरामिड' नीतियों में होता हो। ऐसे ही इस सूचना का उपयोग भी किया जा सकता है कि आयातित सामान गोल्ड और पेट्रोल पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इन रु ज्ञानों को आटफिीशियल इंटेलिजेस के उपयोग से विदेशी मुद्रा के व्यवहार को भी भांपा जा सकता है, और उसी के प्रयोग से बहुत बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित किया जा सकता है।

सतीश पेडणोकर

इसका अंदाजा इसी लगाया जा सकता है कि इसे ''नया तेल' कहा जाने लगा है। सूचना का भण्डार ही धन का स्रेत है। आज सूचना का ज्ञान ही परम ज्ञान है। ऐसे में डेटा ही संपत्ति है। डेटा से व्यक्ति की हर गतिविधि को पता लगाने के लिए अति संवेदनशील तकनीक को प्रयोग में लाया जा रहा है। कृत्रिम प्रज्ञता (आटफिीशियल इंटेलिजेस) का उपयोग करके पता लगाया जा रहा है कि व्यक्ति की उपयोग संबंधी एवं रहन-सहन संबंधी प्राथमिकताएं क्या हैं और उन्हीं के आधार पर मार्केटिंग व्यय किया जा रहा है। ऐसा मार्केटिंग व्यय व्यर्थ नहीं जाता। व्यवसाय में वृद्धि होती है। इस प्रकार डेटा से उत्पन्न सूचना प्राप्त व्यवसाय लाभप्रद स्थिति में हो जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो फाइनेंस में कार्यरत कंपनियों में भारी विदेशी निवेश है। इस क्षेत्र में भी यह सूचना का प्रतिफल हो सकता है। जो पेमेंट रु ज्ञान से विकसित होती ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संकेत विदेश में स्थित कंपनियों को अधिक विश्वस्त रूप से प्राप्त हो जाते हों और उसी का उपयोग ''बॉटम ऑफ पिरामिड' नीतियों में होता हो। ऐसे ही इस सूचना का उपयोग भी किया जा सकता है कि आयातित सामान गोल्ड और पेट्रोल पर कितना पैसा खर्च किया जा रहा है। इन रुझानों को आटफिीशियल इंटेलिजेस के उपयोग से विदेशी मुद्रा के व्यवहार को भी भांपा जा सकता है, और उसी के प्रयोग से बहुत बड़ी मात्रा में लाभ अर्जित किया जा सकता है। इन महत्त्वपूर्ण बातों का संज्ञान लेते हुए आरबीआई ने ''डेटा संप्रभुता' के मद्देनजर वित्तीय सेवा देने वाली समस्त कंपनियों को भारत से संबंधित समस्त वित्तीय डेटा भारत में ही रखने के लिए दिशा-निर्देश दिए। इनका पालन करने की अवधि गत 15 अक्टूबर को समाप्त हुई। उम्मीद की जा रही थी कि शायद आरबीआई कुछ और समय देगा इन दिशा-निर्देशों के पालन हेतु। मगर ऐसा हुआ नहीं। इसीसे इसके प्रति गंभीरता का पता चलता है।

आज भारत में ई-कॉमर्स, इनफार्मेशन तकनीक, सोशल मीडिया, डिजिटल मनोरंजन आदि क्षेत्रों में विदेशी कंपनियों का आधिपत्य है। प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों ही तरीके से। या तो विदेशी कंपनियां अपना व्यवसाय कर रही हैं, या उनके द्वारा पोषित विदेशी निवेश यह कार्य कर रहा है। यही चिंता का विषय भी है। व्यापार करने की छूट एक अलग बात है। डेटा के उपयोग में प्राथमिकता अलग बात। मिसाल के तौर पर अगर वित्तीय पेमेंट वाली कंपनी जान पाए कि कितने लोग भविष्य में किस एयरलाइंस की टिकट अधिक बुक कर रहे हैं, तो यह विश्लेषण निवेश हेतु एक महत्त्वपूर्ण सूचना है। ऐसे में इस प्राइस सेंसिटिव इनफार्म्रेशन का दुरुपयोग हो सकता है। इसी प्रकार किस सिनेमा चेन की टिकट पेमेंट गेटवे से अधिक बुक हो रही है, यह जानकारी भी प्राइस सेंसिटिव कैटेगरी में आएगी। यही नहीं, कार्ड पेमेंट और धारक के मूवमेंट से सुरक्षा संबंधित सूचना भी लीक हो सकती है। कुछ विशेषज्ञ इसे ''कंज्यूमर केंद्रित' मान रहे हैं, जो मेरे विचार से उचित नहीं है। डेटा संप्रभुता सुरक्षा से जुड़ा हुआ यह मामला भी है। आर्थिक सुरक्षा के अलावा नीतियों के सफल होने या न होने की पूर्वसूचना भी डेटा से हासिल हो सकती है। जैसे आयुष्मान भारत या मनरेगा में होने वाली डिजिटल पेमेंट के रु झान से भविष्य के राजनैतिक परिदृश्य को भी भांपा जा सकता है। नीतियों की सफलता सत्ता में दुबारा आने की संभावना को प्रदर्शित करती है। अन्यथा नहीं। यह बहुत संवेदनशील मामला है। इसके अलावा, एक तर्क इस बात का भी दिया गया है कि कानून का अनुपालन कराने वाली संस्थाओं को डेटा हासिल करने में लगातार कठिनाई आ रही थी। डेटा जिस देश में रखा जाएगा उसकी उपलब्धता उस देश के कानूनों के अनुसार ही दी जाती है। अपने देश में हुई किसी लेन-देन की जानकारी हेतु विदेशी सरकार के पास प्रतिवेदन करना कोई अच्छी स्थिति नहीं कही जा सकती जबकि उस लेन-देन में उस देश का कोई नागरिक ही शामिल न हो।इन सब बातों से डेटा के महत्त्व का पता चलता है। जो चीज महत्त्वपूर्ण होती है, वह कीमती भी होती है। कुछ विशेषज्ञों के विचार से भारत डेटा के मामले में विश्व औसत से दुगुनी गति से वृद्धि कर रहा है। इस कीमती डेटा पर हम अपनी संप्रभुता कायम कर सकें तो हम इस नये ''एसेट क्लास' में विश्व में दूसरे बड़े निवेशक होंगे। दूसरी तरफ सूचना के आदान-प्रदान में सुगमता में बाधा की बात को कह कर इसका विरोध भी हो रहा है। मुक्त व्यापार का विरोधी माना जा रहा है। मसला भारत-अमेरिकी संबंधों पर भी प्रभाव डालता दिख रहा है। कुछ अमेरिकी राजनयिकों ने इस संबंध में भारत पर दबाव बनाने की कोशिश भी की है। वीसा और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी पेमेंट कंपनियों ने अभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया है, और वह कुछ टाल-मटोलु रवैया अपना रही हैं, जिसमें प्रमुख है कि डेटा की एक ''मिरर इमेज' दी जा सकती है। आरबीआई और सरकार ने इस सुझाव के प्रति कोई सकारात्मक संकेत नहीं दिया है, और यह उचित ही है। भारत के इस पक्ष को अमेरिकी कंपनी ''डेल' के माइकल डेल ने हालिया इंटरव्यू में उचित मानते हुए कहा है कि डेटा की सुरक्षा और संप्रभुता एक महत्त्वपूर्ण मांग है, जो भारत ने उठाई है। यह मांग नियंतग्र स्थिति धारण कर सकती है, जब अन्य देश भी इसी तरह की मांग करने लगें। हालांकि माइकल डेल का कथन उन देशों के लिए है, जो ''डेटा स्थानीयकरण' के संबंध में उदासीन हैं। चीन, जर्मनी और रूस ''डेटा स्थानीयकरण' के संदर्भ में बहुत पहले ही नियम बना चुके हैं, और वह इस संदर्भ में काफी गंभीर हैं। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि बड़ी चीनी कंपनी अलीबाबा ने भारत के पक्ष का समर्थन किया है। अलीबाबा भारतीय कंपनी पेटीएम में बड़ी निवेशक है, और ''डेटा स्थानीयकरण' का पालन कर रही है। ट्रेड वॉर के बनते माहौल में भारत का यह कदम थोड़ा थोड़ा स्ट्रेटेजिक नजर आ रहा है। इसे पहले उठाया जाना चाहिए था। ट्रंप प्रशासन ही जब मुक्त व्यापार से वापस लौट रहा है, तो भारत को प्रत्येक प्रकार का हक है कि ऐसा कदम उठाने से पीछे न हटे जिसमें वह अमेरिकी दबाव में नजर न आए और अपनी संप्रभुता के सिद्धांत में डेटा को भी समाहित करके उसे संपूर्ण बनाए।

चलते चलते

गैर-जिम्मेदार

आप पच्चीस लाख तक ऐश से खर्च करें। बहुत पहले हेमा मालिनी जी एक बैंक के इश्तिहार में आह्वान करती थीं कि फलां बैंक से कर्ज लो, खर्च करो, राज करो। हेमा जी मेरी मां की उम्र की हैं, मैंने उनकी बात मानकर बहुत लोन लिया, बहुत खर्च किया। वह कर्जदारी अब तक चल रही है,

ई-मेल बॉक्स खुला था, मां ने देख लिया। एक ई-मेल आई थी किसी बैंक से। उसका आशय था कि आपका क्रेडिट कार्ड डिस्पैच कर दिया गया है। आप पच्चीस लाख तक ऐश से खर्च करें। बहुत पहले हेमा मालिनी जी एक बैंक के इश्तिहार में आह्वान करती थीं कि फलां बैंक से कर्ज लो, खर्च करो, राज करो। हेमा जी मेरी मां की उम्र की हैं, मैंने उनकी बात मानकर बहुत लोन लिया, बहुत खर्च किया। वह कर्जदारी अब तक चल रही है, और राज तो कहीं न कर पाया, अलबत्ता, जलील उस कर्ज की वजह से बराबर हुआ। हेमा जी बैंकिंग एक्सपर्ट नहीं हैं, यह बात मुझे बहुत बाद में समझ में आई। खैर, मेरी मां ने मुझे डपटा-कितनी जगह से उधार लेगा। इस बैंक से क्रेडिट कार्ड क्यों लिया। मैंने निवेदन किया-जी मैंने कोई क्रेडिट कार्ड नहीं लिया, किसी भी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई न किया। ये तो अपने आप भेजे जा रहे हैं ईमेल। मां ने फिर मुझे डबल डपटा-बचपन में तुझे जुआ खेलते हुए पकड़ती थी मैं, तब भी तू यही कहता था कि मैं न खेलता। यह तो जुआरी जबरदस्ती खिला देते हैं। मां ने मुझे उधारखाऊ, कर्जाखाऊ घोषित करके बहुत गालियां सुनाई हैं-जिनका संक्षेप में आशय है कि कैसा बेटा है,जो उधार खाकर घर की इज्जत दांव पर लगा रहा है। ई-मेल खंगालते हुए मां के हाथ स्मार्ट शादी डॉट कॉम की पांच ई मेल और हाथ लगीं, जिनमें मुझे प्रस्ताव दिए गए थे कि आप हमारी वेबसाइट के जरिए शादी करवा के देखिए। मां ने अब की बार लगभग पीटते हुए कहा-तुझे शर्म न आती। तेरी बड़ी बेटी एकाध साल में शादी के काबिल हो जाएगी और तू अपनी शादी के चक्कर में पड़ा हुआ है। चरित्रहीन, गैर-जिम्मेदार। मैंने फिर निवेदन किया-जी मैंने कहीं शादी की एप्लीकेशन न डाली। ये स्मार्ट शादी डॉट कॉम वाले जाने किन-किन को अपने प्रस्ताव भेज देते हैं। मां ने फिर मुझे बचपन का ट्रैक रिकॉर्ड याद कराया। आरोप लगाया तू मर्जी से खेलता था जुआ, बाद में ढोंग करता था कि जुआरी जबरदस्ती खिला देते हैं जुआ तुझको। तू उधार खाऊ, तू दूसरी शादी की फिराक में, तेरी तो ऐसी पिटाई करूंगी, पूरा मुहल्ला देखेगा। ओ माई गॉड, ईमेल के अत्याचार और मां की पिटाई से कैसे बचूंगा, कोई बताएगा क्या!

फोटोग्राफी...

मैसुरू में सोमवार को निजी दासारा उत्सव के दौरान ''वज्र मुश्ती कलागा' और ''विजया

लोकतंत्र की पाठशाला

दुनिया के सभी विविद्यालय छात्रों को केवल डिग्री देने का ही काम नहीं करते बल्कि लोकतंत्र की पाठशाला भी रहे हैं। बहस-मुबाहिसे, चर्चा विरोध-प्रतिरोध तथा अभिव्यक्ति की आजादी का भी मंच रहे हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षा शास्त्री, समाजसेवी और राजनीतिज्ञ उन्हीं संस्थानों से निकलते हैं। अक्सर देखा जाता है कि राजनीतिज्ञों का राजनीतिक जीवन कॉलेजों और विविद्यालयों से शुरू होता है, और वे भी चर्चा विमर्श में भाग लेते हैं। इस तरह लोकतांत्रिक मूल्यों के हिमायती होते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश आज के छात्र नेता जब सत्ता में आते हैं, तब लोकतांत्रिक मूल्यों का ही गला घोंटने लगते हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपना राजनीतिक जीवन छात्र राजनीति से शुरू किया था। आज देश के मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। उन्होंने शिक्षा में सुधार के कार्यक्रम लागू करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। लेकिन उनके कार्यकाल में देश के विविद्यालयों में गहरा असंतोष, अशांति और अराजकता का माहौल भी बना है। इतनी अशांति विविद्यालयों में कभी नहीं रही। किसी विविद्यालय में लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोंटा जा रहा हो तो जावड़ेकर मूकदर्शक बने नहीं रह सकते। इसलिए उनका कर्त्तव्य बनता है कि वे हस्तक्षेप करें। लेकिन क्या ऐसा कर रहे हैं? सवाल इसलिए उठाया जा रहा है कि शिक्षकों की मांगों को स्वीकार करने, खाली पद तेजी से एवं न्याय संगत तरीके से भरने की जगह उल्टे उन्होंने एस्मा कानून लगाने की बात कही। इसी 4 अक्टूबर को विविद्यालय अनुदान आयोग ने एक कार्यदल गठित कर दिल्ली विविद्यालय कानून, 1922 में बदलाव लाकर एस्मा के प्रावधानों को शामिल किए जाने संभावनाएं तलाशने का काम किया। यह अलग बात है कि शिक्षकों के भारी दबाव और विरोध के कारण उन्होंने इस कदम को वापस लिया।

उच्च शिक्षा सचिव को तत्काल सफाई देनी पड़ी लेकिन इससे सरकार की नीयत का पता चलता है। पूरी दुनिया को पता है कि सरकार एस्मा कानून लगा कर सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल करने के अधिकार को छीन लेती है, उनकी नौकरियां खा जाती है। पिछले दिनों कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश के शिक्षक समुदाय को संबोधित किया है। क्या इन बातों से मोदी सरकार घबराई हुई है? चाहे इलाहाबाद विविद्यालय हो या अलीगढ़ विविद्यालय-सब जगह असंतोष है। अलीगढ़ विविद्यालय में तो 1200 कश्मीरी छात्रों ने अपनी डिग्रियां लौटाने की बात कही है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? जेएनयू के कुलपति आखिर, किसकी शह पर अलोकतांत्रिक कदम उठा रहे हैं? अदालत तक उनके फैसलों को गैर-कानूनी बता रही है, लेकिन सरकार मूकदशर्क बनी हुई है। दरअसल, आज हमारे उच्च शिक्षण संस्थानों की दुर्गति के पीछे राजनीतिक दलों, गुटों और संगठनों का भी हाथ है, जिसने अध्यापन, पठन-पाठन, शोध कायरे पर पूरा ध्यान न देकर हर चीज का राजनीतिकरण किया है। कांग्रेस और भाजपा की छात्र इकाइयां जिस तरह चुनाव में पैसे बहाती हैं, उससे पता चलता है कि विविद्यालयों में किस तरह की राजनीति चल रही है। मोदी सरकार कांग्रेस की सरकार से अधिक दमनकारी साबित हो रही है। यही कारण है कि एस्मा जैसे कानून को लगाने का ख्याल सरकार के मन में आया है, जो लोकतंत्र के लिए ही नहीं, बल्कि शिक्षा जगत के लिए भी अशुभ है, जिससे समस्या सुलझने की बजाय और विस्फोटक होगी।

सार समाचार

वियतनाम की संसद ने कम्युनिस्ट पार्टी प्रमुख को राष्ट्रपति चुना

वियतनाम की नेशनल असेंबली ने कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव गुयेन फुट्रोंग को मंगलवार को देश का राष्ट्रपति चुन लिया इससे दक्षिणपूर्व एशियाई देश में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के तौर पर उनका प्रभाव और मजबूत होगा। 1960 के दशक में देश के संस्थापक राष्ट्रपति हो ची मिन्ह के अलावा ट्रोंग (74 वर्ष) दोनों पद संभालने वाले वियतनाम के पहले नेता होंगे। वह राष्ट्रपति ट्रान दाई कुआंग का स्थान लेंगे जिनका पिछले महीने निधन हो गया था। वह एक वर्ष से अधिक समय से अस्वस्थ थे। ट्रोंग ने शपथग्रहण समारोह में एक हाथ उठाकर और दूसरा हाथ संविधान पर रखकर देश, जनता और संविधान के प्रति पूरी तरह से निष्ठा रखने की शपथ ली।

पाकिस्तान में ट्रक और वैन की टक्कर में सात लोगों की मौत

कराची। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मंगलवार को तस्करी कर पेट्रोल ले जा रही एक वैन के ट्रक से टकरा जाने पर कम से कम सात व्यक्तियों की मौत हो गयी और समीप में खड़ी तीन कारें एवं एक पुलिस चौकी जलकर नष्ट हो गयीं। इससे एक दिन पहले ही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में दो बसों की आमने-सामने की टक्कर में 20 लोगों की जान चली गयी थी और 30 अन्य घायल हो गये थे। खैबर न्यूज के मुताबिक मंगलवार को एक वाहन क्वेटा की प्रांतीय राजधानी से सिब्बी जा रहा था। उसके एक अस्थायी टैंक में तस्करी के माध्यम से लाया जा रहा पेट्रोल छिपा कर रखा गया था। पुलिस के अनुसार ट्रक से वाहन की टक्कर होने के बाद पांच व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गयी। दो घायलों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। समीप में खड़ी तीन कारें और पुलिस चौकी भी धू-धूकर जलने लगीं। खैबर न्यूज के अनुसार पुलिस चौकी के दो जवान भी घायल हो गये। वे आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे।

सऊदी वाणिज्य दूतावास खशोगी की हत्या क्रूर साजिश का नतीजा: तुर्की

अंकारा। एक अहम तुर्क नेता ने सोमवार को कहा कि इस्तांबुल स्थित सऊदी वाणिज्य दूतावास के अंदर सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की साजिश क्रूरतापूर्वक रची गई थी। तुर्की की सत्तारूढ़ पार्टी 'जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी' (एकेपी) के प्रवक्ता उमर सालिक ने अंकारा में पत्रकारों से कहा, ''बेहद वहशियाना तरीके से साजिश रची गई थी, और हम एक ऐसी स्थिति से रुबरु हैं जहां सबूतों को मिटाने के बेतहाशा प्रयास किए गए हैं।''सालिक का यह बयान तुर्की की तरफ से पहला आधिकारिक संकेत है कि वह मानता है कि खशोगी की हत्या की साजिश पहले ही रची गई थी। उन्होंने कहा, ''यह बहुत ही जटिल हत्या है।'' उन्होंने आगाह किया कि तुर्क सरकार किसी कयासआराई में नहीं जाएगी। उन्होंने कहा, ''(दूसरे) हर कोई कयास कर सकते हैं लेकिन हम कयास नहीं लगा सकते हैं।''उन्होंने सऊदी अरब और तुर्की के बीच मोल-तोल के दावों को खारिज कर दिया और कहा कि यह अनैतिक है। रियाद ने शनिवार को कहा था कि दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए दो अक्टूबर को वाणिज्य दूतावास के अंदर गए खशोगी की ''विवाद'' के दौरान हत्या कर दी गई।

2019 में चुनाव के बाद भारत की तरफ फिर बढ़ाऊंगा दोस्ती का हाथः इमरान

रियाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मंगलवार को कहा कि वह भारत में 2019 के लोकसभा चुनावों के बाद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ एक बार फिर बढ़ाएंगे क्योंकि उनका मानना है कि नयी दिल्ली ने बातचीत की उनकी पेशकश को इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि पड़ोसी देश में चुनाव में पाकिस्तान एक मुद्दा है। रियाद में फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनीशियेटिव फोरम को संबोधित करते हुए खान ने कहा कि पाकिस्तान अपने सभी पड़ोसियों और खासकर भारत और अफगानिस्तान के साथ शांति चाहता है।

सरकारी रेडियो पाकिस्तान ने खान के हवाले से कहा, 'भारत के साथ शांति से दोनों देशों को शस्त्र स्पर्धा में लिप्त होने के बजाय अपने संसाधनों का उपयोग मानव विकास के लिए करने में मदद मिलेगी।' उन्होंने कहा कि इसी तरह अफगानिस्तान में शांति से पाकिस्तान को द्विपक्षीय आर्थिक तथा व्यापार गतिविधियों के लिए मध्य एशियाई देशों तक आसान पहुंच का मार्ग सुलभ होगा।

खान ने कहा कि उन्होंने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन भारत ने उसे ठुकरा दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अगस्त में सत्ता संभालने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया था कि सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) से इतर दोनों के विदेश मंत्रियों की बैठक की जाए।

भारत ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में तीन पुलिसकर्मियों को मार दिया जिसके बाद नयी दिल्ली ने यूएनजीए से इतर विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी। खान

ने कहा कि वह भारत में आम चुनाव संपन्न होने के बाद एक बार फिर दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। भारत में अगले साल आम चुनाव होने हैं।

मदद मांगने मित्र देशों सऊदी अरब, मलेशिया और चीन जाएंगे इमरान खान

इस्लामाबाद (एजेंसी)।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मदद मांगने के लिए तीन मित्र देशों...सऊदी अरब, मलेशिया और चीन की यात्रा पर जाएंगे। मीडिया की खबरों में सोमवार को यह जानकारी दी। खान इन देशों से अपनी नकदी संकट झेल रही सरकार के लिए 13 अरब डॉलर की सहायता की मांग करेंगे। 'डॉन' अखबार ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि खान सोमवार को सऊदी अरब जाएंगे। वह 28 अक्टूबर को दो दिन की मलेशिया यात्रा पर भी जाएंगे। खान तीन नवंबर को चीन की यात्रा पर जा सकते हैं। खबर में कहा गया है कि प्रधानमंत्री खान अगले दो सप्ताह में तीन मित्र देशों की यात्रा पर जा सकते हैं। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से राहत पैकेज मांगा था। खान मंत्रिमंडल के एक सदस्य ने कहा कि प्रधानमंत्री इन देशों के साथ वित्तीय मदद का मुद्दा उठाएंगे क्योंकि पाकिस्तान को मौजूदा आर्थिक संकट से बाहर निकलने के लिए सहायता की काफी जरूरत हैं। इस मंत्री ने कहा कि सरकार को 12 से 13 अरब डॉलर की तत्काल जरूरत है। ''आठ अरब डॉलर हमें विदेशी कर्ज उतारने के लिए और पांच अरब डॉलर सरकार के कामकाज को चलाने के लिए चाहिए।''

रिपब्लिकन लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देते हैं: ओबामा

वॉशिंगटन (एजेंसी)।

डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सत्तारूढ़ रिपब्लिकन्स पर लोगों को एक-दूसरे के

खिलाफ खड़ा करने और देश की वास्तविक चुनौतियों से नहीं निपटने का आरोप लगाया। व्हाइट हाउस छोड़ने के दो साल बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए सबसे ज्यादा समर्थक जुटाने का काम ओबामा ही कर रहे हैं। छह नवंबर को होने वाले मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेटिक पार्टी को बढ़त मिलने की उम्मीद है। नेवाडा में डेमोक्रेटिक पार्टी की चुनाव प्रचार रैली में ओबामा ने कहा, 'सत्ता पर काबिज रिपब्लिकन आपको स्वार्थी बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आप वोट न करें।

मौजूदा चुनौतियों से निपटने की बजाए वे नस्लीय, जातीय एवं धार्मिक विविधता से जुड़े इस देश के इतिहास के कुछ हिस्सों को बर्बाद करना चाहते हैं।''पूर्व राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि रिपब्लिकन लोगों को गुस्सैल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता ने कहा, 'वे विभाजन की अपील करते हैं, फिर वह डराना चाहते हैं और फिर एक समूह को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। वे हमें बताते हैं कि सुरक्षा एवं व्यवस्था तब तक बहाल रहेगी जब तक हम 'उन लोगों' को सत्ता में नहीं आने देते जो लोग हमारे जैसे नहीं दिखते या हम जैसा बोलते नहीं है या हमारी धार्मिक मान्यताओं को नहीं मानते हैं।' ओबामा ने कहा, 'वह 'वास्तविक अमेरिकियों' की बात करते हैं जैसे कि हम में से कुछ, असल अमेरिकी नहीं हैं।'उन्होंने कहा कि जैसे ही चुनाव करीब आता है रिपब्लिकन्स इस तरह की चालें चलने लगते हैं। लेकिन एक स्वस्थ लोकतंत्र में यह सब काम नहीं आता।'

खशोगी को जिस तरह मारा गया, वैसा फिर कभी नहीं होना चाहिए

जकार्ता (एजेंसी)।

सऊदी अरब के विदेश मंत्री आदिल अल-जुबेर ने मंगलवार को कहा कि जमाल खशोगी जैसे आलोचक की हत्या जिस तरह हुई, वैसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने पत्रकार की हत्या के मामले में पूरी तरह जांच की वचनबद्धता जताई। अल-जुबेर ने जकार्ता में इंडोनेशिया के विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, ''सऊदी अरब का नेतृत्व देखेगा कि जांच पूरी तरह हो और सच सामने आए। जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराया जाए।''उन्होंने यह संकल्प भी जताया कि ऐसा तंत्र बनाया जाएगा ताकि, 'इस तरह की घटना फिर कभी न हो।'

इंडोनेशियाई विदेश मंत्री आर मरसुदी ने मंगलवार को कहा कि जकार्ता इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में इस महीने खशोगी की हत्या को लेकर बहुत चिंतित है। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन मंगलवार की शाम तक इस हत्याकांड के बारे में सच सामने रख सकते हैं। एर्दोआन की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रवक्ता उमर सेलिक ने कहा कि अत्यंत बर्बर तरीके से हत्या की साजिश रची गयी थी और इसे छिपाने के लिए बहुत प्रयास किये गये।

सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान के मुखर आलोचक खशोगी (59) दो अक्टूबर को इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में प्रवेश के बाद से लापता हो गये थे। वह वहां अपनी शादी के लिए जरूरी कुछ कागजात लेने गये थे। कुछ दिन बाद तुर्की की सरकार के एक सूत्र ने कहा कि पुलिस को लगता है कि इस्तांबुल भेजे गये एक दल ने उनकी हत्या कर दी और तुर्की के एक अखबार ने 17 अक्टूबर को लिखा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और वाणिज्य दूतावास के अंदर उनकी हत्या कर दी गयी। सऊदी अरब ने दो सप्ताह से अधिक समय तक चुप्पी साधने के बाद शनिवार को कबूल किया कि खशोगी की वाणिज्य दूतावास में एक विवाद के दौरान मौत हो गयी। कई लोगों ने इस बात को खारिज कर दिया।

खशोगी की हत्या के बाद अमेरिका-सऊदी संबंधों में दिख रही दरार

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका पर 11 सितंबर, 2001 को 19 विमान अपहर्ताओं ने हमला किया था, जिनमें से 15 सऊदी अरब के थे। इसके बाद सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ अपने महत्वपूर्ण संबंध को बचाने के लिए लॉबिंग शुरू की। अमेरिका को प्रभावित करने के लिए 10 करोड़ अमेरिकी डॉलर खर्च करने के बाद भी तेल समृद्ध इस देश के लिए अमेरिका के साथ संबंधों पर अब संकट खड़ा हो गया है। ऐसे अमेरिकी सांसद और संस्थान जो सऊदी शहजादे के साथ मित्रता करने के लिए उत्साहित रहते थे और रियाद से खुशी-खुशी धन स्वीकार करते थे, वे अब रियाद से दूरी बना रहे हैं। स्व निर्वासित सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की इस्तांबुल में सऊदी वाणिज्य दूतावास में हत्या होने के बाद सऊदी अरब के खिलाफ अंततराष्ट्रीय स्तर पर आक्रोश उभरा है, जो पिछले वर्षों में शायद ही देखा गया हो। अब अमेरिका के सांसदों ने कभी न सोचे जाने वाले कदम भी सऊदी अरब के खिलाफ प्रस्तावित किए हैं जैसे कि सऊदी अरब के साथ हथियारों की बिक्री को स्थगित और उसके राजदूत को निष्कासित करना। सऊदी अरब अमेरिकी हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार है। हालांकि इस सबके बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने की ही बात कही है। फॉरेन इन्फ्लुएंस ट्रांसपेरेंसी इनिशिएटिव एट द सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिसी के निदेशक बेन फ्रीमैन ने कहा, ''ज्यादातर अमेरिकी सऊदी अरब के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यह देश बड़ा पर्यटन स्थल भी कई वजहों से नहीं है और इस वजह से पीआर फर्मों को अपनी बात रखने में आसानी हो जाती है।' खशोगी के लापता होने के बाद कम से कम चार लॉबिंग कंपनियों ने कहा है कि वे अब सऊदी अरब का प्रतिनिधत्व नहीं करेंगी।

सिंधु जल संधि पर भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करेगा पाकिस्तान: रिपोर्ट

वाशिंगटन (एजेंसी)।

इस्लामाबाद- पाकिस्तान 1960 की सिंधु जल संधि (आईडब्ल्यूटी) को लेकर अपनी चिंताओं पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत के खिलाफ आक्रामक अभियान शुरू करेगा. मंगलवार को मीडिया में आई एक खबर में ऐसा कहा गया. भारत ने पाकिस्तान के अधिकारियों को जम्मू-कश्मीर में दो पनबिजली परियोजनाओं का दौरा नहीं करने दिया, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस मुद्दे पर उसके खिलाफ अभियान चलाने का मन बनाया है.

स्थायी सिंधु जल आयोग पर पाकिस्तान के आयुक्त सैयद मेहर अली शाह ने कहा कि भारतीय जल आयुक्त ने 29 और 30 अगस्त को हुई वार्षिक बैठक में वादा किया था कि सितंबर के अंतिम हफ्ते में जम्मू-कश्मीर में 1,000 मेगावाट की पाकल दुल और 48 मेगावाट की लोअर कलनाई परियोजना के दौरे का प्रबंध किया जाएगा. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में स्थानीय चुनावों के कारण यह दौरा मध्य अक्टूबर तक के लिए टल गया.

डॉन समाचारपत्र की एक खबर के मुताबिक, शाह ने आरोप लगाया कि भारतीय पक्ष ने उसके संशोधित कार्यक्रम का सम्मान नहीं किया और कहा कि राज्य में 20 साल बाद पंचायत चुनाव हो रहे हैं. शाह ने कहा कि उन्होंने निराशा जाहिर करने के लिए एक पत्र लिखा और फिर कुछ दिन पहले अपने समकक्ष से फोन पर बात की. उन्होंने कहा कि फोन पर हुई बातचीत के आधार पर, उन्हें नहीं लगता कि जल्द कोई दौरा होगा.

भारत के अनुरोध पर भी चीन नहीं हुआ टस से मस, अपने 'चहेत' आतंकी पर नहीं लगाएगा लगाम

बीजिंग (एजेंसी)।

चीन ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवादियों की सूची में पाकिस्तानी दहशतगर्द जैश-ए-मौहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को शामिल करने के भारत के अनुरोध पर उसके रूख में कोई बदलाव नहीं आया है. चीन ने कहा कि वह 'मामले के गुण दोष' के आधार पर मुद्दे पर निर्णय करेगा. नई दिल्ली में हुई भारत चीन के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर पहली उच्च स्तरीय बैठक में सोमवार को भारत ने चीन से संयुक्त राष्ट्र में अज़हर को वैश्विक आतंकी के तौर पर नामित करने के लिए लंबित पड़े अनुरोध का समर्थन करने को कहा था.

इस बैठक की सह अध्यक्षता गृह मंत्री राजनाथ सिंह और चीन के स्टेट काउंसलर और सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री झाओ केझी ने की. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चीन स्थायी सदस्य है और इसके पास वीटो की ताकत है. चीन ने बार-बार संयुक्त राष्ट्र में अज़हर को वैश्विक आतंकी की सूची में शामिल करने की भारत की कोशिश को बाधित किया है.

भारत के अनुरोध के बारे में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनइंग से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें दोनों मंत्रियों के बीच बातचीत के ब्यौरे को देखना है. उन्होंने कहा, '' मसूद (अज़हर) को सूची में शामिल करने के भारत के अनुरोध का संबंध है, हम पहले ही कई बार अपना रूख बता चुके हैं.''

चुनइंग ने कहा कि आतंकवाद रोधी मुद्दे पर, चीन हमेशा से अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद रोधी अभियानों में हिस्सा लेता रहा है. हमने हमेशा अपने फैसले मामले के गुण दोष के आधार पर किए हैं.'' प्रवक्ता ने कहा, '' हम पक्षों के साथ क्षेत्रीय शांति एवं स्थिरता बनाए रखने के लिए सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे.'' अज़हर भारत में कई घातक हमलों का आरोपी है. इनमें 2016 में कश्मीर के उरी सैन्य शिविर पर हुआ हमला भी शामिल है जिसमें 17 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई थी.

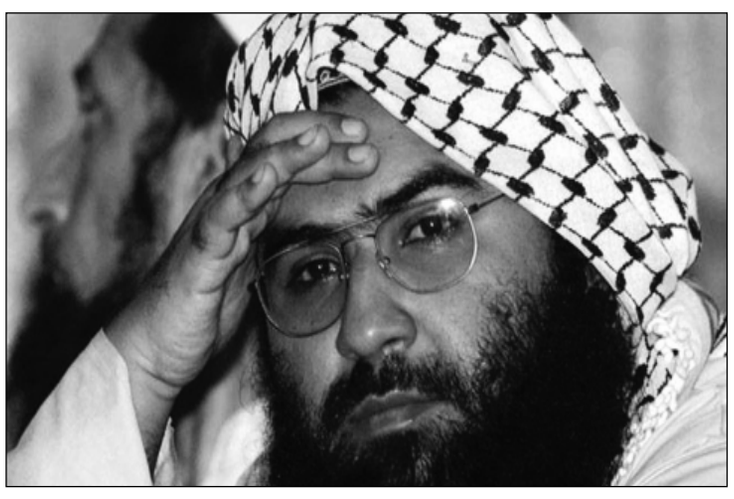

कई दिन तक फोन चलाने से महिला के हाथ का हुआ ये हाल

नई दिल्ली (एजेंसी)।

लगातार लंबे वक्त तक सेलफोन का इस्तेमाल करना कितना नुकसानदेह हो सकता है आप इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चीन की एक समाचार वेबसाइट संघाईस्ट के अनुसार, हुनान के चंगासा में एक महिला ने तगातार 7 दिन तक इतना ज्यादा फोन चलाया कि अब उसकी अंगुलिया सीधी नहीं हो रही थीं। लगातार, दिन-रात मोबाइल पकड़े रहने से उसकी अंगुलियां अब सीधी नहीं हो रही। इस खबर को सुनकर आपको हैरानी जरूरी होगी लेकिन यदि आप भी कई घंटे तक लगातार मोबाइल चलाते हैं जो यह घटना के आपके लिए बड़ी चेतावनी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, महिला एक सप्ताह की छुट्टी पर थी। लेकिन कई घूमने की बजाय वह अपने दोस्तों से लगातार चैटिंग करती

रहती थी। वह सिर्फ सोने के वक्त फोन छोड़ती थी नहीं तो लगातार अपने हाथ में रखती थी। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि फोन महंगा होने के कारण वह उसे हाथ में पकड़कर रखती थी। लेकिन एक दिन जब उसके हाथ में दर्द शुरू हुआ तो अहसास हुआ कि वह उसकी अंगुलिया सीधी नहीं हो रहीं। इसके बाद महिला अस्पताल गई और चेकअप कराने तो डॉक्टरों ने कुछ दवाई देकर उसके हाथ को ठीक किया। इलाज के बाद महिला का हाथ अब ठीक है।

डॉ. हेडगवार बसाहत निवासी कई महीनों से दूषित पानी पीने को मजबूर

सूरत। सूरत महानगर पालिका के उधना जोन क्षेत्र में सिथत डॉ. हेडगवार बसाहत वासी पिछले 4 महीनों से दूषित पानी पीने को मजबूर है। बसाहत वासियों द्वारा इस बात की शिकाय बार-बार किए जाने के बावजूद साउथ जोन के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है।

बसाहत में लगातार कई महीनों से गंदा पानी आने से बसाहत वासी गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे है। मंगलवार को वसाहत के सलीमभाई पटेल ने बसाहत वासियों के साथ मोर्चा निकालकर साउथ जोन के कार्यपालक इंजीनिय को आवेदन पत्र सौंप कर वसाहत में स्वच्छ पानी की आपूर्ति करने की मांग की।

कार्यपालक इंजीनियर को सौंपे आवेदन पत्र में वसाहत वासियों ने कहा है कि हमारे विस्तार डॉ.हेडगवार वसाहत 1, 2, 3 में लगभग 4 महीने से दूषित पानी आ रहा है। जिसकी कई बार लिखित तथा मौखिक शिकायत संबंधित अधिकारियों से की जा चुकी है। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वसाहत में लगातार दूषित पानी की आपूर्ति होने से लोग गंभीर बीमारियों के शिकार हो रहे है। पिछले दिनों धस्तीपुरा इलाके में दुषित पानी पीने के कारण 8 से 10 लोगों की मृत्यु होने का हवाला देते हुए वसाहत वासियों ने कहा कि क्या अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे है कि डॉ. हेडगवार वसाहत में भी लोगों की मौत हो जाए। निवेदन में कार्यपालक इंजीनियर को समस्या की गंभीरता को समझते हुए तत्काल ठोस कदम उठाने की मांग की गई है। वसाहत वासियों का कहना है कि यह वसाहत 23 साल पुराना है जिसमें लगभग सभी प्रांत एवं क्षेत्र के लोग रहते है।

सरथाणा में स्कूल बस और कार के बीच भिड़त

सूरत। शहर के सरथाणा इलाके में मंगलवार दोपहर को एक स्कूल बस और कार के बीच भिड़त हुई। इसमें कार के अगले भाग के पड़खच्चे उड़ गए। दुर्घटना के दौरान बस में स्कूली बच्चे बैठे थे, जो दुर्घटना के बाद जोर-जोर से शोर मचाने लगे। बच्चों को घर भेजने के लिए फौरन दूसरी बस की व्यवस्था कर दी गई थी।

सौभाग्य से इस दुर्घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। सरथाणा विस्तार में पोदार इन्टरनेशनल स्कूल और एक निजि कार के बीच दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में कार के बोनेट के खरपच्चे उड़ गए, परन्तु किसी भी प्रकार की जन हानि नहीं हुई थी। घटना के चलते अफरा तफरी मच गई थी।

पत्रकार के साथ हेड कॉस्टेबल द्वारा दुर्व्यवहार का मामला

ज्यूडिशियल काउंसिल ने पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र

सूरत। लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ मीडिया पर हो रहे लगातार हमले तथा भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा मीडिया कर्मियों को झूठे मामलों में फसाए जाने की बढती घटना को गंभीरता से लिया है। केन्द्र सरकार ने अध्यादेश जारीकर सभी राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पत्रकारों के साथ अभद्रव्यवहार करने तथाउनकों धमकाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जिसके तहत सूरत शहर के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा को ज्यूडिशियल कमिशन द्वारा पत्र लिखा गया है। जिमें पाण्डेसरा जी.आई.डी.सी थाने में तैनात पुलिस हेड कॉस्टेबल संजय प्रभदास पटेल तथा नेफाभाई मुभाभाई ढोलचर क विरुद्ध जांच कर कानून कर्रवाई करने को कहा गया है। विदित हो कि 17 अकटूबर 2018 की सुबह 11 बजे के करीब क्रांति समय के संपादक सुरेश मौर्या ने पांडेसरा जी.आई.डी.सी पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी कि पांडेसरा क्षेंत्र स्थित मणिनगर सोसायटी में कुछ असामाजिक तत्व रहते है जिनकी असलील और अमर्यादित हरकतों के कारण पूरी सोसायटी के लोग परेशान है। इस तरह की शिकायत दिए जाने पर हेड कास्टेबल संजय प्रभूदास पटेल तथा नेफाभाई मुजाभाई ने शिकायत कर्ता को बुराभला कहना शुरु कर दिया और कहने लगे तुम अपना काम देखे पूरे गांव का ठेका लेने की जरुरत नहीं है। अगर तुम इनके खिलाफ फरियाद दर्ज करने की कोशिश करोंगे तो में सामने वाली पार्टी से तुम्हारे विरुद्ध फर्जी मामला दाखिल कराकर ऐसे केस में फसाउंगा की नेतागिरी भूल जाओगे। उपरोक्त पुलिस कर्मियों द्वारा यह पूछे जाने पर कि तुम किस हेसियत से इनके खिलाफ फरियाद कर रहे हो तो सुरेश मौर्या ने बताया कि में एक पत्रकार हुं और क्षेत्र में हो रेह असामाजिक प्रवृतियों पर नजर रखना मेंरा कर्त्तव्य है। इस पर उपरोक्त कर्मियों ने उनका आई कार्ड दिया तो उन दोनों ने कार्ड हाथ से झपट कर छीन लिया और उसे पैरों तले रौंदने लगे।

इन दोनों पुलिस कर्मियों ने सुरेश मौर्या को धमकाते हुए कहा कि यदि मामले को आगे बढाओगेतो तुझ ऐसे मामले में फसाएंगे की तुम्हारी जमानत तक नहीं हो पाएगी। इस घटना के बाद सुरेश मौर्या ने ज्युडिशियल काउंसिल में मामले की जानकारी दी। जिसपर ज्यूडिशियल काउसिल के डायरेक्टर जनरल एडवोकेट राजीव आग्निहोत्री ने सूरत के पुलिस कमिश्नर सतीश शर्मा तथा डिप्टी पुलिस कमिश्नर को पत्रलिखकर मामले की जांच उच्च अधिकारियों से कराने तथा आरोपी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने को कहा है।

पश्चिम रेलवे द्वारा त्योहारों के दौरान गांधीधाम से भागलपुर के लिए विशेष ट्रेन

सूरत। आगामी त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भी ? को देखते हुए पश्चिम रेलवे द्वारा गांधीधाम-भागलपुर विशेष ट्रेन चलायेगी। जिसके मुताबिक ट्रेन सं 09451 गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक विशेष ट्रेन प्रत्येक शुक्रवार को गांधीधाम से 17.40 बजे रवाना होगी एवं रविवार को 18.00 बजे भागलपुर पहुँचेगी। यह ट्रेन 26 अक्टूबर से 16 नव बर, 2018 तक चलेगी। इसी प्रकार वापसी यात्रा में ट्रेन सं 09452 भागलपुर-गांधीधाम साप्ताहिक विशेष ट्रेन प्रत्येक सोमवार को भागलपुर से 06.30 बजे रवाना होगी एवं बुधवार को 08.00 बजे गांधीधाम पहुँचेगी । यह ट्रेन 29 अक्टूबर से 19 नव बर, 2018 तक चलेगी। यात्रा के दौरान यइ ट्रेन दोनों दिशाओं में भचाऊ, समाखियाली, ध्रांगध्रा, अहमदाबाद, नडियाड, दाहोद, रतलाम, भवानी मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, हिंडौन सिटी, बयाना जं., भरतपुर, अछनेरा, मथुरा जं., कासगंज, फर्रुखाबाद, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया सदर, सिवान जं., छपरा, हाजीपुर, बरौनी जं., बेगुसराय, साहेबपुर कमल जं. तथा मुंगेर स्टेशनों पर ठहरेगी। इस ट्रेन में एसी 2 टियर, एसी 3 टियर, शयनयान तथा द्वितीय श्रेणी के सामान्य डिब्बे होंगे। ट्रेन सं या 09451 की बुकिंग 24 अक्टूबर, 2018 से सभी यात्री आरक्षण केन्द्रों तथा आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर शुरू होगी ।

अब अनुसूचित पर अत्वाचार बर्दाश्त नहीं करेगी : रुपाणी

गांधीनगर । मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने सामाजिक सद्भाव को विकास की नींव बताते हुए स्पष्ट रूप से बताया है कि, अनुसूचित जाति-जनजाति, पीड़ितों, दलित वर्गों पर विशेष ध्यान देकर उनको सामाजिक न्याय मिले, सुरक्षा मिले इसके लिए तहसील स्तर से राज्य स्तर तक पूरी व्यवस्था का मोनिटरींग राज्य सरकार की पहली सेवा है। विजय रुपाणी सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा आदिवासी विकास विभाग की राज्य सतर्कता और मोनिटरींग समिति की बैठक अध्यक्षता से संबोधित कर रहे थे। गांधीनगर में आयोजित हुई इस बैठक में उपमुख्यमंत्री नीतिन पटेल, विधानसभा विपक्ष के नेता परेश धानाणी, मंत्रियों में गणपतसिंह वसावा और इश्वर परमार, प्रदीपसिंह जाडेजा तथा सांसद विनोदभाई चावडा और रामसिंह राठवा सहित विधायक उपस्थित हुए । मुख्यमंत्री ने बताया कि, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिवासियों पर के अत्याचार सरकार किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे अत्याचार की घटनाओं में अपराधियों को कड़ी सजा हो और पीड़ितों को सही न्याय-सुरक्षा मिले यह सरकार की प्रतिबद्धता है यह भी उन्होंने बताया है। विजय रुपाणी ने स्पष्ट रूप से बताया है कि, ऐसे अत्याचार की घटना में कन्वीकशन और जुर्माना यह दो पेरामीटर्स होते है इसे सख्ती से लागू करके अत्वाचारों की घटना में कन्वीकशन रेट-सजा का दर बढ़े तथा अपराधियों को कड़ी सजा जुर्माना हो इसके लिए संबंधित विभाग योग्य प्रबंधन करे। मुख्यमंत्री ने आगे बताया है कि, पिछड़ा-दलित-शोषित वर्गों पर अत्याचार रूके, उनको समानता मिले इसके लिए सरकार ही नहीं सभी साथ में मिलकर सामाजिक जिम्मेदारी निभाकर एक होकर अच्छा बनकर सद्भाव का माहौल निर्माण करे यह जरूरी है। बैठक की चर्चा के दौरान बताया गया है कि, राज्य सरकार ने ऐसी जातियों पर के अत्याचार की घटनाओं में सुधार किए गए सहायता के स्तर जारी किए है।

डीजिटल गुजरात के निर्माण क्षेत्र में निश्चित कदम

११.९३ लाख विद्यार्थी को १४७.८६ करोड़ की छात्रवृत्ति

गांधीनगर । आदिवासी मंत्री गणपत वसावा और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री इश्वरभाई परमार ने बताया है कि, डीजिटल गुजरात के निर्माण क्षेत्र में गुजरात ने कई नये आयाम शुरू करके देश को नई दिशा बताई है । अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गैर -आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के स्कूल में पढ़ते विद्यार्थियों को यूनिफोर्म और छात्रवृत्ति की सहायता सीधे उनके अकाउंट में जमा कराई जाती है । मंगलवार को आदिवासी मंत्री गणपत वसावा और आदिवासी राज्यमंत्री रमणभाई पाटकर की प्रेरक उपस्थिति में राज्य के ११.९३ लाख विद्यार्थियों को १४७.८६ करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति सहायता उनके बैंक खाते में सीधा बेनीफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) से जमा कराई गई है । इस बारे में आगे की जानकारी देते हुए मंत्रियों ने बताया है कि, प्रगतिशील गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने ज रूरतमंद लोगों को लाभ सीधा प्राप्त हो इसके लिए विशेष ध्यान केन्द्रित करके समय पर आयोजन किया गया है। इसकी वजह से राज्य में दलाली प्रथा बंद हो गई है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, गैर-आरक्षित आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों की डीजिटल गुजरात पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन प्रस्ताव मंगाकर छात्रवृत्ति मंजूर करने का काम वर्ष २०१८-१९ में शुरू किया गया है। अभी तक में राज्य की स्कूलों में अभ्यास करते यह विद्यार्थियों को कक्षा-१ से १० में छात्रवृत्ति और कक्षा-१ से ८ में यूनिफोर्म सहायता देने की योज ना लागू है । मंत्रियों ने कहा है कि, वर्ष २०१८-१९ में कक्षा १ से ८ के विद्यार्थियों को दी जाती यूनिफोर्म सहायता में वार्षिक ३०० रुपये की वृद्धि की गई होने से अब वार्षिक ६०० रुपये यूनिफोर्म सहायता चुकाई जाती हो वर्ष में प्रिमेट्रीक छात्रवृत्ति और यूनिफोर्म सहायता योजना में करीब ७५०.०० करोड़ रुपये की रकम विद्यार्थियों को मिलेगी।

सूरत। सूरत। मंगलवार की सुबह 10 बजे कांग्रेस प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा और प्रदेश प्रभारी महंती की उपस्थिती में सूरत शहर कांग्रेस समिति द्वारा वार्ड नं 5 फुलपाड़ा, अश्विनी कुमार और दोपहर में वोर्ड नं. 3 सीमाड़ा सरथाणा विस्तार में कांग्रेस आपके द्वारे कार्यक्रम जन सम्पर्क अभियान में शहरी जनों की समस्याओं को सूना और चुनाव के फंड लोगों के पास से लिया।

सुप्रीम के फैसले बाद कलेक्टर भी एक्शन में

रात दस बजे के बाद पटाखे फोड़ने वाले के विरूद्ध कार्रवाई

कलेक्टर इस मामले में अध्यादेश जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया, हालांकि पटाखेप्रेमी जनता में

अहमदाबाद । दीपावली के त्यौहारों में पटाखे फोड़कर की जाती आतिशबाजी में सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशनवाला और लाइसेंस हो तथा उनको पटाखे की बिक्री करने की मंजूरी देने के लिए कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंगलवार को दिए गए एक महत्वपूर्ण फैसले में ऑनलाइन पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाकर रात को ८ से १० बजे तक ही पटाखे फोड़ने की मंजूरी दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अहमदाबाद के जिला कलेक्टर विक्रांत पांडे भी सक्रिय हो गये है। अहमदाबाद कलेक्टर द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के नियमों को सख्ती पालन करके रात को निश्चित समय के अलावा पटाखे फोड़ने वाले के विरूद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करने का बताया गया है। कलेक्टर ने इस मामले में अध्यादेश जारी करने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अहमदाबाद कलेक्टर भी एक्शन में आ गये है, जिसमें पर्यावरण को नुकसान करता पटाखे की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की कवायद शुरू की गई है। इतना ही नहीं, यदि प्रतिबंधित पुराने पटाखे की बिक्री करते विक्रेताओं पर छापेमारी की गई जाएगी । अहमदाबाद कलेक्टर द्वारा रात को दस बजे के बाद पटाखे फोड़नेवाले के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार सख्ती कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई थी। उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दीपावली के त्यौहारों में पटाखे की बिक्री सहित इसकी मंजूरी मामले में मंगलवार को महत्व का फैसला सुनाया है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कम एमिशनवाला और लाइसेंस हो उनको ही पटाखे की बिक्री करने की मंजूरी देने के लिए कहा गया है । इसके अलावा ऑनलाइन पटाखे की बिक्री अवैध माना जाएगा।

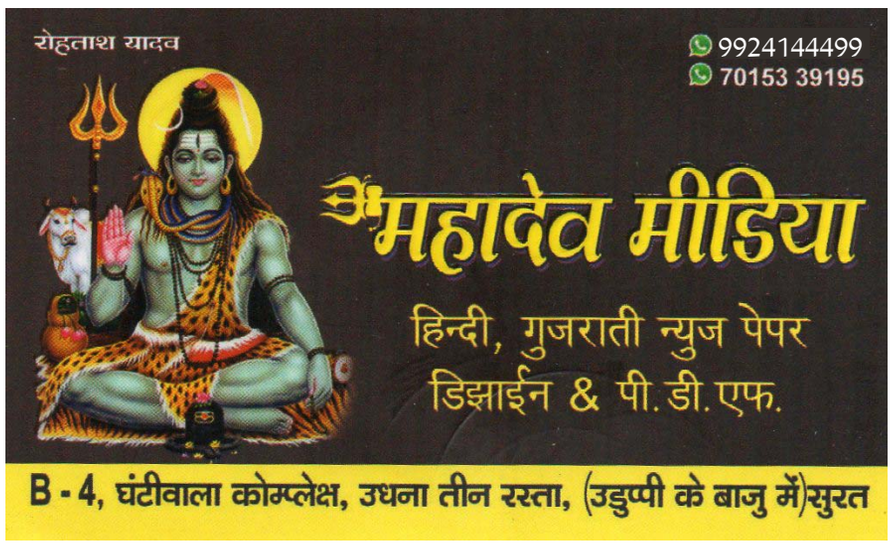

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com